T **खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिये बिहार से प्राप्त लम्बित प्रस्ताव**

2460. **श्री रामदेव भंडारी**: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में सरकारी और निजी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने के संबंध में इस समय केन्द्रीय सरकार के समक्ष लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या हैं?

खाय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी.सिंह देव): (क) खाद्य प्रसंस्करण उदयोग मंत्रालय किसी राज्य में स्वयं किसी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना नहीं करता । अल्कोहलयुक्त पेयों के किण्वन और आसवन व लघु क्षेत्र के लिये आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंस मुक्त हैं और उद्यमियों को सिर्फ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई.ई.एम.) प्रस्तुत करने होते हैं । फिर भी ऐसे उद्योगों के मामलों में जहां औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक हैं अथवा 100 प्रतिशत निर्यात करने वाली यूनिटों या विदेशी सहयोग के लिये अनुमोदन दिये गये हैं । उदारीकरण से लेकर अक्टूबर,1995 तक बिहार से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु 22 औद्योगिक उद्यमी प्रस्तुत किये गये थे जिनमें से 5 को स्वीकृति दी गई हैं । प्राप्त हुये तीन और प्रस्तावों के संबंध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी हैं ।

Wailing List for Telephones in Karnataka

2461. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the total number of persons on the waiting list for telephones in Karnataka Circle and Bangalore Telephones till 30.11.95;

(b) what is the total number of new linos provided during 1994-95 and till 30.11.95 in 1995-96;

(c) which are the exchanges in Karnataka Circle, where the waiting lists have not been cleared for two years and above: and

(d) the reasons for this delay, exchange-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Total number of persons on the waiting list Karnataka Circle as on 30.11.95 is 1,69,919 which includes 80,282 for Bangalore Telecom.

(b) Total number of new lines provided are as follows;

During 1994—95=1,36,008 lines &

During 1995—96=56,070 lines (upto 30.11.95)

(c) Details are given as per annexure. *[See* Appendix 175, Annexure No. 57]

(d) The shortages of resources like equipment, cables and line materials arc the main reasons for delay in provision of telephone connections for all these exchanges.

Enquiry into the Stampede at Nagpur

2462. SHRI V. RAJESHWAR RAO: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a), what, is the. present position of the enquiry after one year of the death of hundreds of Gowaris in a stampede in Nagpur on 23rd November, 1994;

(b) by when the enquiry is likely to be completed; and

(c) what steps arc being taken to expedite die enquiry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (PROF. M. KAMSON): (a) to (c) Following the incident of stampede in Nagpur on the 23rd November, 1994, a Commission of Enquiry had been appointed by the Government of Maharashtra under the Chairmanship of Shri Justice S.S. Dani of the Bombay High Court. The Commission was required to submit its report to the State Government of Maharashtra within a period of six months from the date it was set up. The term of the Comission has since been extended by the State Government upto the 5th June. 1996.